Research Journal of Language, Literature and Humanities E-ISSN 2348-6252
Vol. **11(1),** 14-20, January **(2024)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

को वड–19 सुरक्षा जाल के रूप में मनरेगा की भू मका

वकास यादव
समाज शास्त्र वभाग, महात्मा गांधी काशी वद्यापीठ वश्व वद्यालय, वाराणसी, भारत
vikasyadava001@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 29th July 2023, revised 1st October 2023, accepted 11th December 2023

सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme – MGNREGA) ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजी वका सुरक्षा एवं स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान कया है। यह एक मूल्यवान रोज़गार उपकरण और सुरक्षा जाल रहा है, जिसकी पुष्टि को वड महामारी के दौरान उभरे प्रवासी संकट के समय भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लये एक लये के करने आकलन का प्रभावकारिता की कार्यक्रम इस में रूप के साधन उन्मूलन गरीबी से रूप वशेष , वाल अध्यक्षता की सन्हा अमरजीत स चव वकास ग्रामीण पूर्व है। कया गठन का स मतिी इस स मति की पहली बैठक नवंबर गया दिया समय का माह तीन लये के देने सुझाव अपने इसे और थी हुई आयोजित में 2022था। इस आलेख में अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्र मकों की भू मका, प्रवासी संकट व रोज़गार वहीनता से निपटने में मनरेगा की भू मका, उत्पन्न चुनौतियाँ तथा उनसे निपटने में अल्पका लक व दीर्घका लक उपायों पर चर्चा की जाएगी।

मुख्य शब्द:

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अ धनियम यानी मनरेगा एक बार फर से चर्चा के केंद्र में है। चर्चा का पहला कारण यह है क हाल ही में प्रस्तुत कये गए केंद्रीय बजट 2023- करोड़ हजार 60 लये के मनरेगा ने सरकार केंद्र में 24 89 गए कये आवंटित वर्ष वगत क जो हैं कये आवंटित रूपए है। कम काफी से रूपयों करोड़ 400 हजार[1] कई वर्षों से इस योजना के लये आवंटित कये जा रहे बजट में लगातार कटौती की जा रही है जिसका वरोध हो रहा है, जब क इसके लाभों से हम सभी कोरोना काल में अवगत हैं।

इस योजना के चर्चा में आने का दूसरा कारण काम कर रहे श्र मकों की ऑनलाइन हाजिरी से संबं धत है। इसमें नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर)NMMS बार दो में दिन से ऐप (श्र मकों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का प्रावधान कया गया है। यह प्र क्रया जियो टै गंग के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा ही की जा सकती है।[2] माना जा रहा है क इससे इस योजना में पारद र्शता आएगी और मशीनों का उपयोग बंद होकर वास्त वक लोगों को ही रोजगार मलेगा। हालाँ क इस व्यवस्था के वरो धयों का तर्क यह है क गाँवों में बेहद कमजोर मोबाइल नेटवर्क से तरीके इस कारण के अभाव के नेटवर्क / वापस इसे :अत हैं आती समस्याएँ बहुत में लगाने हाजिरी चाहिये। जाना लया

मनरेगा योजना की उच्च मांगों के बावजूद (जैसा आ र्थक सर्वेक्षण 2021-22 में भी प्रकट हुआ) वत्त वर्ष 2022-23 के बजट में मनरेगा के लये आवंटन नराशाजनक रहा है। अ खल भारतीय कसान सभा और नरेगा संघर्ष मोर्चा (NSM) जैसे संगठनों ने मनरेगा के लये आवंटन की अपर्याप्तता को लेकर चंता जताई है।

मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। योजना का प्राथ मक उद्देश्य कसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबं धत अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वत्तीय वर्ष में के दिनों 100 2022 है।वर्ष देना गारंटी की रोज़गार- के मनरेगा तक 23तहत 15. श्र मक स क्रय करोड़ 4रहे हैं।

मनरेगा क्या है?

मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अ धनियम है। इसे भारत सरकार द्वारा लागू में 2005) नरेगा नाम इसका तब तथा था गया कयाNREGA 2010 था। ( ) मनरेगा बदलकर नाम इसका मेंMNREGA था। गया दिया कर (क था यह उद्देश्य का करने लागू को योजना इसि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सदस्यों को वर्ष में रोजगार गारंटीयुक्त का दिन 100 हों। इच्छुक के करने श्रम अकुशल जो सके जा करवाया उपलब्ध

ऐसे क्षेत्र जो सूखाग्रस्त हैं अथवा जहाँ जनजातीय आबादी अ धक है वहाँ है। गया कया प्रबंध का रोजगार के दिनों 150 का को मनरेगानूनी स्तर पर रोजगार की गारंटी देने वाला वश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम भी माना जाता है।

मनरेगा की रूपरेखा

कार्य का कानूनी अ धकार :i .पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के वपरीत मनरेगा का उद्देश्य अ धकार ढाँचे आधारित- निर्धनता चरम से माध्यम के के कारणों का समाधान करना है। ii. लाभा र्थयों में कम होनी महिलाएँ तिहाई-एक कम-से- iii चाहिये।. मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अ धनियम ,1948 के तहत राज्य में कृ ष मज़दूरों के लये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप कया जाना चाहिये।

मांगयोज प्रेरित-ना: मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है क इसके तहत कसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के से रूप कानूनी की पाने काम भीतर के दिनों 15 उसे पर होने वफल जिसमें ,है प्राप्त गारंटी सम र्थत है। जाता कया प्रदान 'भत्ता बेरोज़गारी'

अ धनियम में आरंभ कये जाने वाले कार्यों की सफारिश करने का अ धकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम50 कम-से-% उनके द्वारा ही निष्पादित कया जाता है।

समयबद्ध गारंटी: i. काम के लए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ii. यदि 15 दिवस के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता का नकद भुगतान करना होगा, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान का दायित्व राज्यों का होगा।

वकेंद्रीकृत योजना: i. परिवार को पंजीकरण के लए स्थानीय ग्राम पंचायत में ल खत या मौ खक रूप से आवेदन करना होगा। ii. सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड पर नरेगा के तहत काम करने के इच्छुक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की तस्वीर होगी। iii. निष्पादन के लए कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों को आवंटित कया जाना है।

महिला सशक्तिकरण: i. जिन लोगों को काम आवंटित कया गया है उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए। ii. वत्तीय वर्ष 2008-09 में महिलाओं की भागीदारी 48% थी। iii. 2008 में त मलनाडु (80%) और केरल (84%) में सबसे अ धक महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई थी।[3]

अनुमेय कार्य: जल संरक्षण और जल संचयन (30%), सूखा प्रू फंग (25%), बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य (18%), भू म वकास (15%), ग्रामीण संपर्क (12%)

ग्रामीण आजी वका के समर्थन में को वड-19 महामारी के दौरान मनरेगा की भू मका

को वड-19 महामारी 2019 के दौरान शुरू हुई और 2020 के प्रारं भक वर्ष में गंभीर हो गई। सरकार ने मार्च 2020 के दौरान पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। यह एक दुःस्वप्न है जहां लोगों का रिवर्स पलायन शुरू हुआ और शहरी, शहरों से अपने गांवों कीओर वापस चल दिए।[4] अस्तित्व की स्थिति के साथ, अ धक संख्या में लोगों ने अपना जीवन और रोजी-रोटी चलाने के लए दहाड़ी मजदूरी के लए मनरेगा योजना में काम करना शुरू कया। शहरी क्षेत्रों से वापस ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन के कारण मनरेगा में काम की मांग बढ़ी। इस तथ्य पर वचार करते हुए घोषणा की बजट उच्च लए के योजना ने सरकार , लाख एक में 2021 और करोड़ 71000 लगभग में 2020 जो की -रेखा चत्र) क जैसा है गया पहुंच तक करोड़1 गया दिखाया में (है।[5] लोगों को आसानी से काम मले और समय पर वेतन मले ने सरकार से दृष्टि इस , बजट बढ़ाया।

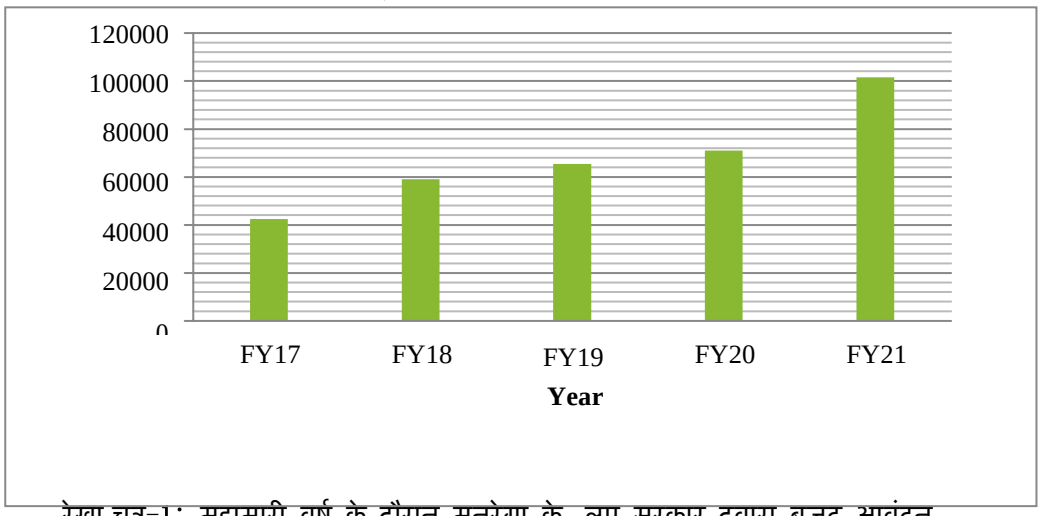

रेखा चत्र-1: महामारी वर्ष के दौरान मनरेगा के लए सरकार द्वारा बजट आवंटन

वर्ष 2020 के दौरान कार्यों की संख्या में भी वृद्ध हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उच्च श्रम बल का प्रमाण है। जैसा क (रेखा चत्र-2) में दिखाया गया है, पछले वर्षों की तुलना में कार्यों की संख्या 202 लाख तक बढ़ा दी गई।[6] पूर्व-को वड की तुलना में मजदूरी रोजगार के परिवारों वाले करने पूरे दिन 100 संख्या कुल की में भारी वृद्ध हुई है जिनकी संख्या 68, 81, 176 व्यक्ति हैं। महामारी के दौरान वतरित कुल मजदूरी जो अंततः मनरेगा कार्यक्रम पर ग्रामीण आजी वका निर्भरता के बारे में बताती है (रेखा चत्र-3)। वर्ष 2017 में मजदूरी में 160 से बढ़कर वर्ष 2020 में 205 हो गई, जिससे रुपये के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है और आने वाले दिनों में बढ़कर 260 रुपये हो सकता है (रेखा चत्र-4)।

महामारी को वड 19 के दौरान मनरेगा में लगे श्र मकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां मनरेगा की एक और महत्वपूर्ण भू मका है, जो को वड-19 के समय में वशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, यह ग्रामीण क्षेत्रों में श्र मकों को काम पर रखने के लए अनुबंध की शर्तों को स्था पत करने के लए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है।[7] यह श्र मकों के लए तापमान की जांच, मास्क, हाथ धोने की सु वधा, न्यूनतम दूरी, उ चत जलयोजन सुनिश्चित करने आदि मनरेगा जैसी सुर क्षत स्थितियों को सुनिश्चित करने के लए कदम उठाता है। इसका मजदूरी दरों और काम की परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण होता है।

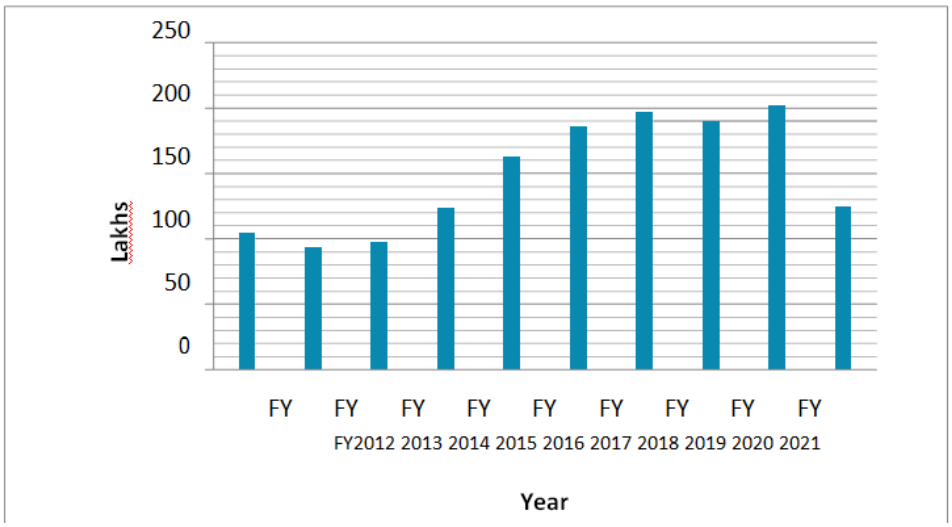

रेखा चत्र2–: मनरेगा से पहले और बाद में कए गए कार्य

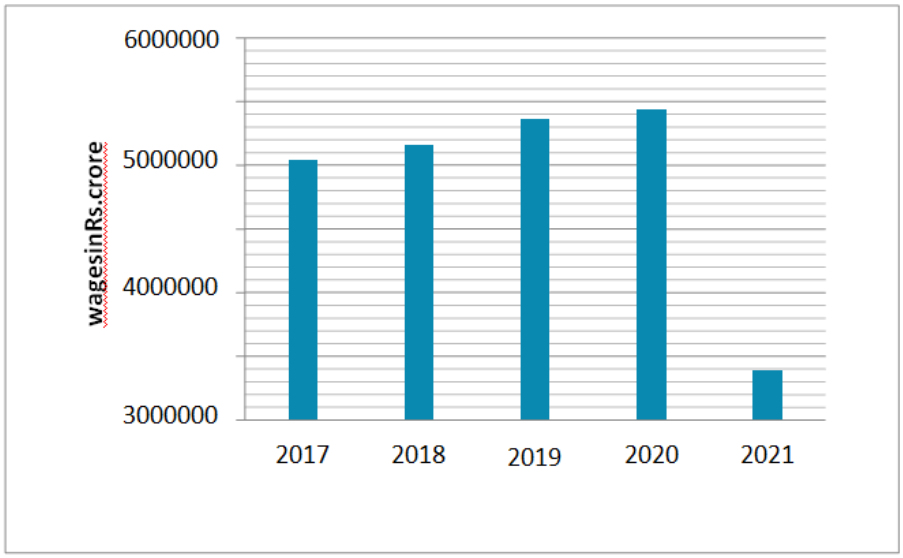

रेखा चत्र–3: महामारी के दौरान वतरित कुल मजदूरी

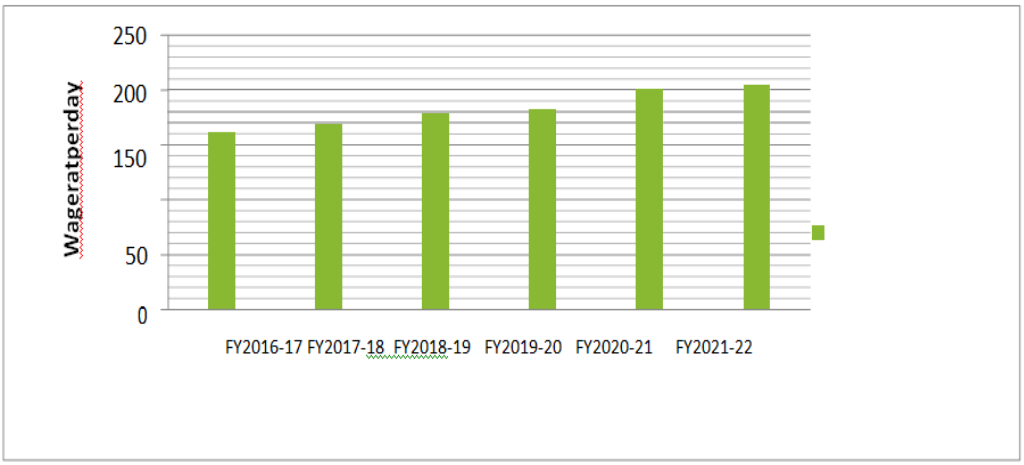

रेखा चत्र-4 प्रति दौरान के महामारी :दिन मजदूरी दर गई हो रुपये 205 बढ़कर से रुपये 180

सरकार बढ़ी हुई मजदूरी के साथ काम को दिन 100 ?में दिशा की करने दिन 200 बढ़ाकर से

जैसा क अनुमान है क लाखों श्र मक रोजगार के लए मनरेगा पर निर्भर हैंउस , से सरकार ने कार्य दिवसों को या 150 से 100 था। दिया कर शुरू सोचना में बारे के बढ़ाने तक दिनों 200 50, रोज़गार कल्याण गरीब साथ के आवंटन के करोड़ 000 प्रवासी लौटे घर दौरान के तालाबंदी उद्देश्य जिसका , अ भयान है। करना प्रदान रोज़गार को मजदूरों[8] इस योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश ओ डशा और झारखंड , राजस्थान , प्रदेश मध्य , के नौकरियों की प्रकार 25 इसमें हैं। शा मल राज्य छह जैसे है प्रावधान का देने रोजगार का दिनों 125 को प्रवा सयों साथ , वृक्षारोपण , बागवानी , आवास ग्रामीण , निर्माण सड़क जिसमें , आंगनवाड़ी , संचाई और संरक्षण जल पंचायत भवन और जल जीवन मशन जैसे कार्य शा मल हैं।

ग्रामीण भारत के वकास में मनरेगा की भू मका: i. वर्ष 2005 में इस योजना के लागू होने के बाद से ही इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में आ र्थक वकास के साथ मज़दूरों के अ धकारों की जागरूकता, कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृ द्ध आदि के द्वारा ग्रामीण वकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। ii. इस योजना के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही आवेदक को रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है, 15 दिनों के भीतर रोज़गार न मलने की स्थिति में आवेदक को भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। ii. इस योजना के तहत रोज़गार प्राप्त करने वालों में एक-तिहाई (1/3) महिलाओं का होना अनिवार्य है, अतः इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के माध्यम से समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायता मली है। iv. इस योजना के तहत आवेदक को स्थनीय स्तर (5 कमी. की सीमा में) पर रोज़गार उपलब्ध करा कर ऐसे बहुत से लोगों को आ र्थक रूप से स्वतंत्र बनाने में सहायता मली है जिनके लये कन्हीं कारणों से रोज़गार हेतु शहरों में पलायन करना संभव नहीं था। ग्रामीण स्तर पर आधारित संरचना के वकास में भी इस योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

ग्रामीण रोज़गार पर को वड-19 का प्रभाव: i. देश में को वड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लये लागू लॉकडाउन के तहत अन्य उद्योगों/व्यवसायों से अलग मनरेगा के लये कोई वशेष छूट प्रदान नहीं की गई थी। हालाँ क राज्यों को सोशल डस्टें संग (Social Distancing) को बनाए रखते हुए योजना को चालू रखने के निर्देश दिये गए थे।[9] ii. वर्तमान में मनरेगा के तहत देश के व भन्न राज्यों में प्रतिदिन की मज़दूरी औसतन 209 रुपए और वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी के साथ यह योजना गरीबी में रह रही एक बड़ी आबादी के लये आजी वका का मुख्य साधन तथा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ (Backbone) मानी जाती है। iii. वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत 7.6 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान कया गया है और वर्ष 2020-21 में लगभग 5.5 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत रोज़गार उपलब्ध कराया गया था।[10] iv. लॉकडाउन के कारण मं डयों के बंद होने और कृ ष उपज की आपूर्ति बा धत होने का प्रभाव इससे जुड़े रोज़गारों पर भी पड़ा

है। v. को वड -19 के कारण उद्योगों के बंद होने से बड़ी संख्या में भारत के व भन्न शहरों से गाँवों की तरफ मज़दूरों का पलायन हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की कमी और कामगारों की अ धकता तथा प्रतिस्पर्द्धा के कारण ग्रामीण असंगठित क्षेत्र (दिहाड़ी, कृ ष मज़दूर आदि) की मज़दूरी में कमी आई है। vi. शहरों से होने वाले पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरों की वृ द्ध के बीच मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत रोज़गार की कमी होना एक बड़ी चंता का वषय है। vii. मार्च 2020 में केंद्रीय वत्त मंत्री ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मज़दूरी में 20 रुपए प्रतिदिन की वृ द्ध करने की घोषणा की थी, परंतु को वड-19 के कारण इस योजना के तहत रोज़गार न उपलब्ध होने की स्थिति में मज़दूरों को इस वृ द्ध का लाभ नहीं मल पाएगा।[11] viii. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही को वड -19 के मामले न हों परंतु यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह एक बड़ी समस्या बन सकती है।

वैश्विक महामारी को वड-19 के कारण भारत ही नहीं वश्व के अ धकांश देशों में लॉकडाउन के वकल्प को अपनाया गया। उस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्र मक वर्ग को पलायन जैसी गंभीर समस्या से दोहोना चार- पड़ा। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने व पाने रोज़गार , महानगरों से कस्बों और गाँवों में आशा की जीने जीवन बेहतर परंतु है देखा होते पलायन ओर कीउस समय महानगरों से गाँवों की ओर हो रहा पलायन नि को स्थिति चंताज़नक संदेहः रहा कर उत्पन्नथा। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन)Reverse Migration है। दी संज्ञा की (

सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य 'महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है' । बड़ी संख्या में प्रवासी श्र मकों का गाँव की ओर प्रवासन हुआ। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम-धंधा बंद होने की वजह से श्र मकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों कलोमीटर दूर अपने घर जाने के लये पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा। इस प्रवासी संकट को दूर करने के लये, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अ भयान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में मनरेगा के लये 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित कया।

अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्र मकों की भू मका : i. भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्र मकों की आय, देश की जीडीपी की लगभग 6 प्रतिशत है। ii. ये श्र मक इसका एक तिहाई यानी जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत घर भेजते हैं। मौज़ूदा जीडीपी के हिसाब से यह रा श 4 लाख करोड़ रुपए है। iii. यह रा श मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओ डशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है। iv. वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4 प्रतिशत की वा र्षक वृ द्ध दर्ज की गई थी, तो वहीं वर्ष 2001 से 2011 के बीच इसकी वा र्षक वृ द्ध दर 4.5 प्रतिशत रही। इन आँकड़ों से पता चलता है क प्रवासन से श्र मकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ। v. श्रम गहन उद्योगों अर्थात ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटोपार्ट्स सेक्टर में बड़ी तादाद में श्र मक काम करते हैं। vi. जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्र मकों को बोनस, इन्क्रिमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज़, आने-जाने का कराया और कैंटीन जैसी सु वधाएँ देकर कंपनियाँ इन्हें अपने साथ जोड़कर रखना चाहती हैं।

मनरेगा की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही हैं? i. वर्ष2022 - 23के आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के माध्यम से1 1 करोड़ से अ धक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार मनरेगा ने को वड लॉकडाउन के समय हुए आय के नुकसान के20 -80% तक हिस्से को भरने का काम कया था। अर्थात को वड के समय जब शहरों में रोजगार में संलग्न लोग जब गाँवों की तरफ लौटे तो मनरेगा ने उनके जी वकोपार्जन में महत्वपूर्ण भू मका निभाई।ii . मनरेगा योजना के द्वारा महिला सशक्तिकरण को भी बल मला है। ग्रामीण महिलाओं के पास आय के स्रोत न होने के कारण कई बार वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाती और लगभग पूरी तरह से अपनी आवश्यकताओं के लये घर के पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। मनरेगा द्वारा उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।iii . मनरेगा लोगों को चरम गरीबी की स्थिति से निपटने में भी सहायता प्रदान कर रहा है क्यों क इसमें वर्ष में न्यूनतम है प्रावधान का रोजगार दिन 100 का भत्ते बेरोजगारी में स्थिति की मलने न के रोजगार तथा सफलतापूर्वक ने मनरेगा प्रकार इस है। गया कया प्रावधान निकालकर बाहर से गरीबी चरम को लोगों में संख्या की लाखों

सम्मा एकनित जीवन जीने में सहायता प्रदान की है।iv . मनरेगा में प्राप्त रोजगार के अवसरों के माध्यम से अनुसू चत जाति और अनुसू चत जनजातियों की आ र्थक स्थिति में सुधार हुआ है। मनरेगा के माध्यम से इनका रोजगार के लये शहरों की ओर होने वाला पलायन कम हुआ है।v . मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में पर्याप्त सुधार देखने को मले हैं। इसके द्वारा तालाबों के निर्माण और संरक्षण द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा मला है के सड़कों ग्रामीण , वकास अन्य प्रकार इसी है। मली गति को संपर्कों से निर्माण इस भी में कार्योंसे अत्यंत सहायता प्राप्त हुई है।vi . इस योजना के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत मजबूती प्राप्त हुई है क्यों क इससे पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं और लोकतांत्रिक वकेंद्रीकरण को बढ़ावा मला है।

वर्ष 2022-i :उपलब्धियाँ की 23. 11.37 करोड़ परिवारों को रोज़गार मला। ii. 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोज़गार सृजित कया गया है, जिसमें से: 56.19% महिलाओं के लये थे, 19.75% अनुसू चत जाति के लये थे, 17.47% अनुसू चत जनजाति के लये थे।

मनरेगा के तहत नई पहलेंi :. 'अमृत सरोवर' : देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/जीर्णोद्धार करना।ये सतह और भू मगत दोनों स्तरों पर जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे। ii. 'जलदूत' ऐप: इसे 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार कसी ग्राम पंचायत में जल स्तर का मापन करने के लये सतंबर 2022 में लॉन्च कया गया था। iii. MGNREGS के लये लोकपाल: MGNREGS के कार्यान्वयन से संबं धत व भन्न स्रोतों से प्राप्त शकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लये फ़रवरी 2022 में 'लोकपाल ऐप' लॉन्च कया गया।

मनरेगा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

भ्रष्टाचार: मनरेगा की प्रमुख चुनौतियों में भ्रष्टाचार को पहले स्थान पर रखा जा सकता है। कई राज्यों में लाखों की संख्या में फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड्स पाए गए। कई मामलों में देखा जाता है क बड़ी मात्रा में फर्जी हाजिरी लगा दी जाती है। इससे सरकार द्वारा आवंटित धन उन लोगों के पास न जाकर जो क पात्र हैं उन लोगों के पास चला जाता है जो क अपात्र हैं।

अपर्याप्त बजट आवंटन: वगत कई बार से मनरेगा के बजट में हो रही कमी को चंता के रूप में देखा जा रहा है क्यों क अ धकांश अकुशल ग्रामीण गरीबों का जीवन इस योजना से सीधे प्रभा वत होता है। हालाँ क इस वषय पर केंद्र सरकार का तर्क यह है क मनरेगा एक माँग आधारित योजना है और जैसे जैसे- कम इस लये जाएगा दिया बढ़ा आवंटन ही वैसे आएगी माँग पड़ेगा। नहीं प्रभाव कोई इसपर का बजट

मजदूरी का समयसेन मलना: एक सर्वे के अनुसार लगभग 78 बार कई इससे हैं। पाते हो नहीं पर समय भुगतान प्रतिशत है देता दिखाई भाव भी का निराशा में श्र मकों प्रति के मनरेगा अपनी श्र मक कारण के मलने न पर समय भुगतान क्यों क ही साथ पाते। कर नहीं पूर्ति की आवश्यकताओं तात्का लक को दर की महंगाई देखते हुए वर्तमान मजदूरी दर को भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

इसे वर्तमान मानकों पर निर्धारित करने की आवश्यकता है। अ धकांश राज्य मनरेगा द्वारा निर्दिष्ट 15 दिनों के भीतर मज़दूरी वतरण करने में वफल रहे हैं। इसके अलावा मज़दूरी , लये के देरी में भुगतान केश्र मकों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इसने योजना को मांग-संचा लत के बजाय आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया गया है और इसके कारण श्र मकों ने इसके तहत कार्य करने में रु च खोनी शुरू कर दी है। वत्तमंत्रालय की एक स्वीकारोक्ति के साथ ही पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं क मज़दूरी भुगतान में देरी की स्थिति अपर्याप्त धन का परिणाम है।

काम का समय से न पूरा हो पाना: मनरेगा की चौथी समस्या है काम का समय से न पूरा हो पाना तथा कार्यों की गुणवत्ता का बेहद खराब होना। इन्हें भी हम भ्रष्टाचार से ही जोड़कर देख सकते हैं। कई बार जल्दी समाप्त हो जाने वाले कामों को केवल इस लये काफी लंबे समय तक धीमी गति से जारी रखा जाता है ता क भुगतान अ धक मल सके जिसका अ धकांश हिस्सा फर्जी

जाॅब कार्ड वालों के पास जाता है। साथ ही घटिया साम ग्रयों के प्रयोग से नि र्मत होनी वाली योजनाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और वे लंबे समय तक उपयोग के लायक नहीं रह पातीं।

पंचायतीराज संस्थान की अप्रभावी भू मका :बेहद सी मत स्वायत्तता के साथ पंचायती राज संस्थान)PRI इस (में सकने कर लागू से तरीके कुशल एवं प्रभावी को अ धनियम हैं। नहीं सक्षम

अधूरे कार्यों की बड़ी संख्या :मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी की स्थिति नज़र आई है और परियोजनाओं का निरीक्षण भी अनिय मत रहा है। इसके साथ ही के मनरेगा , भी निर्माण संपत्ति और गुणवत्ता की कार्य संपन्न तहत है। समस्याजनक

जॉब कार्ड का निर्माण :फर्जी जॉब कार्डों की मौजूदगी फर्जी , कार्डों जॉब और होने गुम के प्र वष्टियों ,करने शा मल को नामों देखी भी समस्याएँ अन्य कई जैसी देरी में करने प्र वष्टियाँ में हैं। गई

निष्कर्ष:

भारत सहित वश्व के तमाम देश कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे थे और धीरे आ र्थक धीरे-रहे बढ़ ओर की संकटथे। इस आ र्थक और स्वास्थ्य चुनौती को देखते हुए कई प्रकार के आ र्थक उपायों की घोषणा की गयी। भारत सरकार द्वारा घो षत उपाय दैनिक आधार पर चुनौतियों का सामना कर रह रहे मज़दूरों की दृष्टि से स्वागत योग्य था।

महामारी ने वकेंद्रीकृत शासन के महत्व को पैदा कया है। ग्राम पंचायतों को कार्यों की मंजूरी के लए पर्याप्त संसाधन, शक्ति और जिम्मेदारियां प्रदान करने, मांग पर काम प्रदान करने और भुगतान में कोई देरी नहोयह सुनिश्चित करने के लए मजदूरी भुगतान को अ धकृत करने की आवश्यकता है। रिवर्स माइग्रेशन के पैमाने ने मनरेगा रोजगार की मांग पैदा की है। ग्रामीण गरीबों की आजी वका पर मनरेगा की पहुंच और प्रभाव दोनों को ध्यान में रखते हुए योजना का वस्तार कया जाना चाहिए।

कई तरह की चुनौतियों के बावजूद यह कहा जा सकता है क मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार ,उन्मूलन गरीबी , ,न्याय सामाजिक ,कमी में पलायन ,सशक्तिकरण महिला तरीके प्रभावी में क्षेत्रों जैसे निर्माण के ढाँचे आधारभूत ग्रामीण इस क है की बात इस आवश्यकता अब है। गया कया काम से प्रभावी को चुनौतियों व भन्न और भ्रष्टाचार व्याप्त में योजना तरीके से समाप्त कया जाए और इसके दायरे में ग्रामीण वकास से जुड़े अन्य कारकों को भी शा मल कया जाए ता क यह उन उद्देश्यों को और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाए जिनके लये इस योजना की परिकल्पना की गई थी।

सन्दर्भ सूची :

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजी वका मशन (2020-21). वा र्षक रिपोर्ट।. ग्रामीण वकास मंत्रालय।
2. नारायणन सुधा .एस ,साहा और .सी ओल्डिजेस ,)2022(. क्या वर्कफ़ेयर काम करता है-को वड ?19 के दौरान भारत की रोजगार गारंटी. जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ,34)1(, 82-108.
3. सूद) र व अनुषा ,2021(. मोदी सरकार क्या मनरेगा के तहत मजदूरी के जाति पुन र्वचार पर भुगतान आधारित-करेगी. द प्रंट। यूआरएल : https://theprint.in/india/governance /modi-govt-to-rethink-caste-based-payment-of-wages-under-mgnrega-says-aware-of-problems/747506/Sood.
4. नंदी) देबमाल्या ,2021(. केंद्रीय बजट ग्रामीण रोजगार की समस्या का समाधान करने में वफल रहा।. भारत वकास समीक्षा। यूआरएल : https://idronline.org/the-union-budget-fails-to-address-the-problem-of-rural-employment/Nandy,Debmalya.2021.
5. नायरशोभना ,)2022(. ग्रामीण रोजगार योजना के सामाजिक ऑ डट में देरी।. द हिंदू। यूआरएल: https://www.thehindu.com/news/national/mahatma-gandhi-rural-employment-scheme-social-audits-

marred-by-delays/article65886687.ece? homepage= trueNair, Sobhana.2022.

6. लोखंडे) गुंडीमेडा .एच और .एन ,2021(. मनरेगा : -को वड में भारत19 लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले प्रवा सयों के लए गारंटी शुदा शरण ।. द इं डयन इकोनॉ मक जर्नल, 69(3), 584-590. doi: https://doi.org/10.1177/00194662211 023848

7. कुमार) .एम ,2020). ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा का गला घोंटनाक :ो वड-19 लॉकडाउन के दौरान मनरेगा ।. एस एस ई आर मोनोग्राफ,20 (2).

8. गुप्ता.एम , डी) .2020(. मोदी सरकार को एम जी एन आर ई जी एस शहरी संस्करण के लए 'कमी की धन' है। रही दिख. द प्रंट।,अक्टूबर। 6

9. घोष) .के ,2020(.FY 20-21 में अगस्त तक ग्रामीण कल्याण पर खर्च पछले - अ धक सबसे में वर्षों 5 डेटा। सरकारी. मनी कंट्रोल। अक्टूबर 1।

10. अग्रवाल) .वी ,पैकरा और .ए ,2020(. मनरेगा मज़दूरी इतनी कम क्यों है?. भारत के लए वचार। 5 अक्टूबर , 2020.
यूआरएल:https://www.ideasforindia.in/topics/poverty - inequality/why-are-mnrega-wages-so-low.html

11. आचार्य) .डी ,2020(. बिहार चुनाव की श्र मकों प्रवासी : थोड़ी नरेगा , लए के मतदाताओं नाराज़ से वापसी है। करता प्रदान सहायता. यूआरएल: https://30stades.com/2020/ 06/10/covid-19-lockdown-migrant-pressure-driving-innovations-in-mgnrega-india/